विशेष आर्थिक क्षेत्र को राहत संभव

नई दिल्ली | सौरभ शुक्ल

केंद्र सरकार देश में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से बजट में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानि एसईजेड को लेकर नए ऐलान करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इन कारोबारियों को घरेलू बाजारों में माल सप्लाई करने पर लगने वाले आयात शुल्क में छूट मिल सकती है। साथ ही कंपनियों को भारतीय मुद्रा में पेमेंट लेने की इजाजत दी जा सकती है।

दरअसल सरकार चाहती है कि देश में एक ऐसा कारोबारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें आयात और निर्यात के मोर्चे पर संतुलन बना रहे। इसमें एसईजेड में ऐसे तमाम मोर्चे हैं जहां पर कारोबारियों की लंबे समय से सुधार की मांग की जाती रही है। इस बाजट में दिए गए प्रस्तावों पर सरकार गंभीरता से मंथन में जुटी है। जानकारी के मुताबिक इस बजट में सरकार इन कारोबारियों को भारतीय घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने की छूट देगी। पहले जो भी कंपनियां घरेलू बाजार में सामान बेचती थी उन्हें अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी चुकानी होती थी। लेकिन बजट में उन्हें इस ड्यूटी को चुकाने पर छूट दी जा सकती है।

यही नहीं इन कंपनियों को विदेशी मुद्रा के बजाए अब भारतीय मुद्रा में ही पेमेंट लेने की भी छूट मिल जाएगी जिससे उन्हें अपनी कारोबारी गतिविधियां चलाने में आसानी हो सकेगी।

बजट उम्मीदें

- भारतीय मुद्रा में पेमेंट लेने की भी इजाजत दी जा सकती है
- घरेलू बाजारों में लगने वाले आयात शुल्क में छूट संभव